



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 257]

No. 257]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1997/आषाढ़ 5, 1919

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1997/ASADHA 5, 1919

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन न्यास)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1997

सा. का. नि. 344 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम, 1997 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची-1

नव मंगलूर पत्तन न्यास (शैक्षिक सहायता अधिनियम 1997)

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 (38 आफ 1963) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल, नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (छात्र शिक्षा भत्ता) विनियम 1980 और नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम 1980, जो दिनांक 27 मार्च 1980 के भारत सरकार का राजपत्र

(असाधारण) में सा. का. नि. 160(अ) व सा. का. नि. 159(अ) में प्रकाशित है, में संशोधन और समेकन लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के अधीन केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो,

## 1. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ :

- (1) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास (शैक्षिक सहायता) विनियम 1997 कहा जाएगा।
- (2) उक्त विनियम उसके भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

## 2. लागू होना :

- (1) ये विनियम प्रासंगिक कार्य, रोजाना मजदूर या अंशकालिक समय के लिए नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर पत्तन के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।
- (2) पत्तन के वे कर्मचारी जो केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में प्रतिनियुक्त हैं, या भारत में विदेशी सेवारत हैं—इन विनियमों के तहत शैक्षिक सहायता लेने के पात्र हैं बशर्ते कि संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार या विदेशी नियोक्ता से प्रतिनियुक्ति अथवा विदेशी सेवा से संबंधित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया हो।

परिभाषाएँ : इन विनियमों में जब तक प्रसंग के अनुसार किसी अन्य बात की अपेक्षा न हो तब तक :

- (1) “मंडल” का वही अर्थ होगा जो महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 में निर्धारित है।

- (2) "कर्मचारी" का अर्थ है पत्न का कर्मचारी।
- (3) "छात्र" का अर्थ है पत्न के कर्मचारी के बच्चे जिसमें सौतेले और गोद में लिए बच्चे भी शामिल हैं जो पूर्णतः कर्मचारी पर अवलंबित हैं।
- (4) "हायर सेकेंडरी" अथवा "सीनियर सेकेंडरी कक्षाएँ" अर्थात् कक्षाएँ XI और XII और 10+2+3 योजना के तहत की कक्षा XII और उसके समतुल्य भी शामिल हैं जैसे उपाधि पूर्व कक्षा अथवा इंटरमीडियेट तकनीक, या पालिटिकल कालेज बशर्ते कि बालक ने वैसी कक्षा में शामिल होने के पहले सेकेंडरी या उसकी समतुल्य परीक्षा पास की हो न कि उच्चतर सेकेंडरी परीक्षा।
- (5) "प्राथमिक कक्षाएँ" अर्थात् I से V तक की कक्षाएँ, लेकिन किण्डरगार्टन अथवा नर्सरी कक्षाएँ शामिल नहीं।
- (6) "मान्यता प्राप्त स्कूल" अर्थात् सरकारी स्कूल अथवा सरकारी अनुदान सहित या रहित कोई शैक्षणिक संस्थाएँ जिन्हें केन्द्र या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन या विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त है या कोई शैक्षणिक प्राधिकार जिसका कोई अपना क्षेत्राधिकार हो, इन उद्देश्यों के लिए वरिष्ठ शिक्षा स्तर को ही स्कूली शिक्षा मानी जानी चाहिए।
- (7) "सेकेंडरी कक्षाएँ का अर्थ है कक्षा VI से X"
- (8) "शिक्षा शुल्क" का अर्थ है देय शिक्षा शुल्क और वास्तविक अदायगी, जिसमें सम्मिलित है—
  - (1) विज्ञान शुल्क
  - (2) प्रयोगशाला शुल्क, विज्ञान शुल्क अलग से लिया नहीं जाता तो।
  - (3) विशेष शुल्क, जो विशेष अतिरिक्त विषय "कृषि" पर लगता है।
  - (4) संगीत जैसे विषय, जो नियमित स्कूली पाठ्यक्रम का अंग है या कोई विषय जिसका कार्यानुभव बढ़ता के अनुसार प्रायोगिक अनुभव की आवश्यकता है। तो उसके लिए लगाने वाले कोई शुल्क।

बशर्ते कि यदि विज्ञान विद्यार्थी से लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क विज्ञानेतर विद्यार्थियों से लेने वाले शुल्क से भी, ज्यादा है, विज्ञान शुल्क जिसका अलग से किए जाने पर भी, जहाँ तक इन आदेशों का संबंध है, शिक्षा शुल्क में सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

स्पष्टीकरण : "शिक्षा शुल्क" में ये सम्मिलित नहीं हैं :—

- (1) घरेलू विज्ञान निधि शुल्क।
- (2) पुस्तकालय शुल्क।
- (3) क्रीडा शुल्क।
- (4) प्रवेश शुल्क और।
- (5) पाठेतर कार्यक्रम शुल्क।

सामान्य शर्तें :—

#### 4. पात्रता :

विनियम संख्या 11 से 24 तक के प्रावधानों का पालन होने पर, पत्न के सभी कर्मचारी प्रासंगिक अथवा दैनिक मजदूरी आधारित अथवा अंशकालिक कार्य पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर, वेतन सीमा की पाबंदी न रखते हुए छात्र शैक्षिक सहायता, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रवासी रियायत लेने के लिए पात्र हैं।

5. (1) यदि पति-पत्नी दोनों पत्न के कर्मचारी हैं और जिनपर विनियम लागू हैं, तो छात्र शिक्षा भत्ता अथवा शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवासी रियायत जैसी स्थिति हो, में से कोई एक ही स्वीकार्य है।

पत्न के कर्मचारी का पति या पत्नी पत्न के बाहर सेवारत हो तो कर्मचारी विनियम के तहत उक्त भत्ता या प्रतिपूर्ति या रियायत सभी मिलेगा यदि उसका पति/पत्नी अपने नियुक्तता से वैसा कोई भत्ता या प्रतिपूर्ति या रियायत नहीं लेता है। इसके संबंध में उस कर्मचारी से एक घोषणा पत्र लेना जरूरी है।

6. (1) छात्र शैक्षिक भत्ता या प्रतिपूर्ति या शिक्षा शुल्क या छात्रवासी रियायत मंडल के कर्मचारी को कार्यरत अथवा निलंबनावधि में या असाधारण छुट्टी सहित, छुट्टी में रहते समय स्वीकार्य है।

बशर्ते कि कोई अवधि जो अकाय दिवस घोषित हुई हो, तो कर्मचारी उस अवधि के लिए भत्ता प्रतिपूर्ति/रियायत के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) यदि किसी कर्मचारी के शिक्षा वर्ष के दौरान मृत हो जाने या सेवा निवृत्ति त्यागपत्र, कार्यमुक्ति, पदव्युति या निष्कासन से सेवा समाप्त हो जाने पर भत्ता अथवा प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवासी रियायत उसी शिक्षा वर्ष, जिसमें घटना घटी है, के अंत तक स्वीकार्य है।

7. छात्र शिक्षा भत्ता, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवासी मात्र 5 और 20 वर्ष के बीच की आयु वाले बच्चों को स्वीकार्य है। मंडल के कर्मचारी अपने बच्चे के लिए एक ही कक्षा में दो से अधिक शैक्षणिक वर्षों के लिए छात्र शैक्षिक भत्ता, शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवासी रियायत के लिए पात्र नहीं हैं।

8. इन विनियमों के अधीन सहायता 3-12-1987 तक जनमें 3 बच्चों को स्वीकार्य है और इसके बाद पैदा हुए बच्चों के लिए वह दो तक सीमित है।

बशर्ते कि मंडल के कर्मचारी अपने किन्हीं बच्चों को छात्र शैक्षिक भत्ता और अन्य किन्हीं को आवासीय रियायत के लिए मांग रखने पर, कुल बच्चों की संख्या जिनके लिए भत्ता अथवा रियायत दी जा रही है दो से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. छात्र शैक्षिक भत्ता, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अथवा छात्रवासी रियायत, जो भी लागू हो, मंडल के कर्मचारी को उसके बच्चों के लिए सभी प्राप्त होगा जब वह बच्चा स्कूल को नियमित रूप से जा रहा हो।

बशर्ते कि सकारणी छुट्टियों के अलावा यदि एक महीने से भी ज्यादा समय अनुपस्थित रहने पर, स्कूल के रोल (बही) में बच्चे का नाम रहते हुए भी, कोई भत्ता शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति या रियायत किसी भी संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है।

10. छात्र शैक्षिक भत्ता, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति अथवा छात्रावासी रियायत, जैसी स्थिति हो, मंडल के कर्मचारी के बच्चों को कोई छात्रवृत्ति होने के बावजूद भी स्वीकार्य है बशर्ते कि यदि छात्रवृत्ति मिल जाती है तो शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति/छात्रावासी रियायत उतना ही स्वीकार्य है जितना वास्तविक रूप से अदा किया गया है।

#### छात्र शिक्षा भत्ता :

11. (1) मंडल के कर्मचारी छात्र शिक्षा भत्ता लेने तभी पात्र बनता है जब वह अपने बच्चे को अपने को तैनात/निवासीय स्थल, जहां अपेक्षित स्तर का स्कूल न रहने कारण उस स्थल से बाहर के स्कूल को भेजने में विवश हो जाता है।

(2) इस आदेश हेतु निम्नलिखित स्कूलों को अपेक्षित स्तर के स्कूल के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए,

(क) जहां तक ऑग्लो इंडियन बच्चों का प्रश्न है, स्कूल जिसका ऑग्लो इंडियन संस्थान द्वारा संचालन न होता हो या स्कूल जो भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद से संबद्ध न हो,

(ख) स्कूल जो किसी धार्मिक संस्था द्वारा संचालित है। जिससे कि बच्चे को किसी धार्मिक परंपरा से नियंत्रित होकर स्कूल में धार्मिक क्रम-नियमों सख्ती से लागू किया जा रहा हो और,

(ग) स्कूल जहां बच्चे को अपनी भाषा से भिन्न एक भाषा द्वारा शिक्षा दी जाती हो।

**विवरण :** (1) बच्चे की भाषा का मतलब है बच्चा जिस स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता रहा हो वहां का शिक्षा माध्यम और बच्चा यदि पहली बार स्कूल में दाखिल हो रहा है तो, जन्म से या दत्तक से उसकी मात्रभाषा।

**विवरण :** (2) छात्र शैक्षिक भत्ता की स्वीकार्यता निर्धारण किसी स्कूल विशेष में किसी पाठ विशेष के मौजूद न रहने के आधार पर न करके स्कूल का स्तर अर्थात् प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी का सीनियर सेकेंडरी और शिक्षा माध्यम एवं बच्चों की भाषा को ध्यान में रख कर निर्धारण करना चाहिए।

12. पतन के कर्मचारी को भत्ता तभी स्वीकार्य होगा जब आवश्यक स्तर का स्कूल अपनी जगह उपलब्ध नहीं है और उस स्तर का कोई स्कूल जो निकट में हो जहां स्कूल आरंभ होने के पहले पहुँचने या दिन का स्कूल बंद होने के बाद बहुत देर न होते हुए वापस आने के लिए बस या रेलगाड़ी की यात्रा के लिए एक घंटे से ज्यादा समय लगता हो।

13. पतन के किसी कर्मचारी के किसी ऐसी जगह से, जहां आवश्यक स्तर का कोई स्कूल नहीं है, दूसरी जगह जहां वैसा स्कूल उपलब्ध है, स्थानांतरण किए गए हो और यदि वह अपने संबंध में पहली जगह के लिए भत्ता लेता रहा हो, तो उस स्कूल का शैक्षिक वर्ष की समाप्ति तक उसे वह भत्ता मिलता रहेगा बशर्ते कि उसी स्कूल में वह बच्चा उस अवधि में पढ़ाई कर रहा हो।

14. पतन के कर्मचारी के बच्चे को, उसकी तैनाती की जगह या निवास के उस आवश्यक स्तर के स्कूल में, कोई रिक्ति न होने या कोई

अन्य कारणों पर प्रवेश नहीं मिला, जिसके कारण बच्चे को कर्मचारी की तैनात/निवासीय जगह से दूर के स्कूल जाना पड़ा तो कर्मचारी को यह मानकर भत्ता दिया जाना चाहिए कि आवश्यक स्तर का कोई स्कूल उस जगह में नहीं है।

**विवरण :** बच्चों को स्कूल में दाखिल करते समय चाहे वह सत्र का आरंभ हो या मध्य, रिक्तियों की उपस्थिति का निर्धारण, स्कूल के प्राधिकारियों द्वारा जारी किए प्रमाण पत्र के आधार पर न करके उस क्षेत्र के सक्षम शैक्षिक प्राधिकारियों से चर्चा के आधार पर करना चाहिए।

15. कर्मचारी जो भत्ता प्राप्त कर रहा है, चार माह से अधिक न होते हुए, किसी भी समय वह भत्ता लेने का हकदार होता है।

(1) छुट्टी पर जब कर्मचारी अपने बच्चे, जिस के लिए भत्ता प्राप्त हो रहा है, के यहां जाकर उसके साथ रहता हो या निलंबन या अस्थायी अंतरण पर हो।

(2) जब बच्चा कर्मचारी के साथ आकर रहता है बशर्ते कि चिकित्सा करने वाले एक पंजीकृत चिकित्सक द्वारा यह प्रमाण पत्र हो कि बीमारी के कारण बच्चे का अध्ययन से दूर रहना पड़ रहा है, और

(3) जब बच्चा अवकाश के दौरान कर्मचारी के साथ आकर रहता है बशर्ते कि बच्चे का नाम स्कूल बहियों में जारी रहे।

16. कर्मचारी को भत्ता निम्नलिखित दरों पर लागू होगा—प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाएँ—I से XII तक रु. 50/- प्रति माह प्रति बच्चा।

17. (1) यह भत्ता कर्मचारी को वर्ष भर के लिए स्वीकार्य होगा भले ही अवकाश के दौरान कोई शिक्षा-शुल्क भुगतान न किया गया हो।

(2) यदि बच्चा माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक के अंतिम परीक्षा में सफल होता है तो कर्मचारी को यह भत्ता उस महीने के अंत तक, जिस महीने में परीक्षा पूर्ण हो गई हो अथवा वह माह जिसके अंत तक शाला शुल्क लिया जाता हो स्वीकार्य होगा।

(3) यदि बच्चा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक की अंतिम परीक्षा में फेल हो जाता है लेकिन पुनः अध्ययन आरंभ करता है तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी को यह भत्ता बीच के अवकाश की अवधि के लिए लागू होगा बशर्ते कि अवकाश अवधि के शुल्क का भुगतान किया गया हो।

#### शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति :

18. कर्मचारी अपने बच्चे के देय तथा वास्तविक रूप से अदा किए गए शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा बशर्ते कि इन अधिनियमों के अंतर्गत के कोई छात्र शिक्षा भत्ता उसे स्वीकार्य न हो।

19. अपने बच्चे के संबंध में देय और वास्तविक रूप में अदा किए गए शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते कि निम्नानुसार हो :

(अ) कक्षा I से X तक—रु. 20/- प्रति माह प्रति बच्चा।

(आ) कक्षा XI से XII तक—रु. 50/- प्रति माह प्रति बच्चा।

(इ) शारीरिक विकलांग और बुद्धिमाध्य बच्चों के संबंध में I से XII कक्षा रु. 50/- प्रति माह प्रति बच्चा।

**टिप्पणी :** IX से XII कक्षा में विज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रु. 5/- तक प्रति माह "विज्ञान शुल्क" शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की जाएगी।

20. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विश्वविद्यालय की उपाधि पूर्व/इंटरमीडियेट कालेज के प्रथम वर्ष या तकनीक कालेज या पॉलिटेक्निक या पत्राचार पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए जाने वाले शुल्क विश्वविद्यालय से संबंधित कालेज द्वारा लगाए शुल्क पूर्ण रूप से प्रतिपूर्ति की जाएगी बशर्ते कि ये दरें सरकारी कालेज द्वारा संबंधित सम-कक्षाओं के लिए निर्धारित दरों तक सीमित हों। यदि पॉलिटेक्निक के दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए संशोधित शिक्षा पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा न्यूनतम अर्हता हो और विद्यार्थी संशोधित पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में दाखिला लेता हो तो उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष की कक्षाओं के लिए शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी।

21. इन आदेशों में किसी बात के होते हुए भी, शारीरिक विकलांग अथवा बृद्धिमाध्य बच्चों के संबंध में किसी कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

(अ) जिस संस्था में बच्चा पढ़ रहा है वह या तो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ शासित अथवा प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त या अनुमोदित या अनुदानित हो।

(आ) प्रभारित शुल्क केन्द्र या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन, जैसी स्थिति हो, द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

**स्पष्टीकरण :** यदि कोई संस्था मान्यता प्राप्त या केन्द्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित प्रशासन द्वारा अनुदानित है प्रभारित शुल्क उनके द्वारा अनुमोदित नहीं है तो शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रति माह रु. 50/- के सीमित दर पर होगी।

#### छात्रावास रियायत :

22. कर्मचारी प्रति माह प्रति बच्चे पर रु. 150/- दर की रियायत प्राप्त करने का हकदार होगा। अपने स्थानांतरण के कारण कर्मचारी यदि अपने बच्चे को आवासीय स्कूल के छात्रावास में रखता है जो उसके नियुक्त स्थान/अथवा निवास से बहुत दूर रहता है, तो उसे प्रति माह प्रति बच्चे के लिए रु. 150/- दर पर रियायत स्वीकृत होगी।

लेकिन, छात्रावास में दाखिल लेने की तारीख स्थानांतरण की तारीख से पहले हो तो और वह दाखिला स्थानांतरण की प्रत्याशा में की गई हो, तो छात्रावासी रियायत स्थानांतरण लागू होने की तारीख से किया जाएगा। छात्रावासी रियायत 10+2 स्तर तक उन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में जहां 10+2+3 प्रणाली प्रचलित हो तथा उच्च माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में इस बात के रहते हुए भी देय होगी कि बच्चे चाहे केन्द्रीय विद्यालय में पढते हो या अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में।

24. यदि कर्मचारी द्वारा अपने बच्चे के संबंध में छात्र शिक्षा भत्ता लिया जा रहा हो तो उसे छात्रावासी रियायत देय नहीं होगी।

#### छात्र शिक्षा भत्ता अदायगी/शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति और छात्रावासी रियायत के लिए विधि

25. कर्मचारी जो छात्र शिक्षा भत्ता, शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति छात्रावास रियायत लेना चाहता है, उसे निर्धारित प्रपत्र 1, 2, 3 और 4 में,

जो भी लागू हो, प्रमाण पत्र के साथ आवेदन सबसे पहले कार्यालय प्रधान को और उसके बाद प्रतिवर्ष मार्च और जुलाई माह में आवेदन देना होगा। जहां कर्मचारी स्वयं कार्यालय प्रधान हो तो वह अपने अच्च अधिकारी को आवेदन करेगा।

**टिप्पणी :** किसी कर्मचारी को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए उस संस्था, जहां बच्चा पढ़ रहा हो, के प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है। लेकिन, प्रारंभिक दावे की स्वीकृति के लिए स्कूल द्वारा दी गई नकद रसीद या बैंक जमा वाउचर का प्रतिपूर्ण, यदि कर्मचारी ने बैंक के माध्यम से शुल्क चुकाया हो, शिक्षा शुल्क की वास्तविक अदायगी के लिए पर्याप्त प्रमाण हो सकता है।

उसके बाद के संदर्भों में, कर्मचारी द्वारा शिक्षा शुल्क पर व्यय जारी रहने संबंधी घोषणा पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए। कर्मचारी से यह भी प्रमाणित करने को कहा जाना चाहिए कि उसका बच्चा/बच्चे वास्तव में मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा/रहे हैं और शिक्षा शुल्क के लिए वे वास्तविक रूप से खर्च कर रहे हैं।

26. किसी कर्मचारी के संबंध में उसके कार्यालय प्रधान तथा कार्यालय प्रधान के संबंध में उससे अगले उच्च अधिकारी, जो भी लागू हो, आवश्यक पृष्ठताछ के बाद, भत्ते की स्वीकार्य राशि दर्शाते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा जिसके आधार पर भत्ता दिया जाना चाहिए।

बशर्ते कि छात्र शिक्षा भत्ते के संबंध में, तीन माह से अधिक न होने वाली अवधि के लिए, अस्थाई आधार पर लिए जा रहे भत्ते, ऊपर बताए गए सत्यापन लंबित रहते हुए स्वीकार्य हैं। लेकिन इसके लिए संबंधित कर्मचारी से यह घोषणा पत्र लेना होगा कि यदि सत्यापन के परिणाम स्वरूप यह साबित हो जाता है कि विनियम 12 में बताने के अनुसार आवश्यक स्तर का स्कूल तैनाती/निवास स्थान में या उसके पास है, तो उसके दिए गए भत्ते को वापस देना होगा।

इसके अतिरिक्त यह है कि कार्यालय प्रधान या उसके बाद के उच्च प्राधिकारी जो भी हो, अपने विवेक पर, आर्वाधिक अंतरालों में इन आदेशों के अधीन लागू सहायता/रियायतों के संबंध में जांच करेगा।

27. कार्यालय प्रधान को वेतन बिल पर यह प्रमाणित करना होगा कि वेतन बिल में दर्शित कर्मचारी से संबंधित विनियम सं. 26 के अनुसार का प्रमाण पत्र लिया गया है।

28. एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर्मचारी यदि छात्र शिक्षा भत्ता या छात्रावासी रियायत के लिए पात्रता रखता है तो उसे नए स्थान पर फिर से नया प्रमाण पत्र पेश करना होगा।

29. कार्यालय प्रधान प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत तथा प्रतिपूर्ति किए गए दावों का हिसाब रखेगा तथा उन्हें पत्तन के कर्मचारी द्वारा दी गई जानकारी और प्रमाण पत्र, दावों की संस्तुति पर पूरक के रूप में शैक्षिक प्राधिकारियों द्वारा जारी रसीदें, या कोई अन्य दस्तावेजों के साथ वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। लेखा-कागजातों का रखरखाव फार्म सं. 5 के अनुसार रहेगा।

[फा. सं. पी आर-12016/40/94-पी ई]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT****(Ports Wing)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th June, 1997

**G.S.R. 344(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the New Mangalore Port Trust (Educational Assistance) Regulations, 1997 made by the Board of Trustees for the Port of New Mangalore Port Trust and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE**

**New Mangalore Port Trust (Educational Assistance)  
Regulations, 1997**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963) the New Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the approval of the Central Govt., under Section 124 of the above Act, the following Regulations to amend and consolidate the New Mangalore Port Trust Employees (Children's Educational Allowance) Regulations, 1980 and the New Mangalore Port Employees (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1980 published GSR 60(E) and GSR 159(E) in the Official Gazette of India Extraordinary, dated 27th March, 1980.

**1. Short title and commencement :**

(1) These Regulations may be called New Mangalore Port Trust (Educational Assistance) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force with effect from the date of publication in the Gazette of India.

**2. Applications :**

(1) These Regulations shall apply to all employees of the Board except persons in casual or daily rated or part time employment.

(2) Employees of the Board deputed to Central/State Govt. of on foreign service in India would be eligible to drawal of educational assistance under these orders from such Central/State Govt. or foreign employer, provided provision to this effect is expressly made in the terms of deputation or foreign service.

**3. Definitions :** In these regulations, unless the context otherwise requires :

(i) "Board" shall have the same meaning assigned in the Major Port Trusts Act, 1963.

(ii) "Employee" means an employee of the Board.

(iii) "Child" means a child of an employee of the Board and includes a step child and an adopted child who is wholly dependent on the employee.

(iv) "Higher Secondary or Senior Secondary Classes" means Classes XI and XII and includes Classes upto the equivalent of XII under the 10 + 2 + 3 scheme like Pre-University class or the first year class of an Intermediate College, a Technical College, or a Polytechnic provided the child has passed the Secondary or equivalent but not the Higher Secondary Examination before joining such class.

(v) "Primary Classes" means Classes I to V but does not include Kindergarten or Nursery classes.

(vi) "Recognised School" means Govt. School or any educational institution whether in receipt of Govt. aid or non-recognised by the Central or State Govt. or Union Territory Administration or by a University or a recognised educational authority having jurisdiction over the area where the institution is situated. For the purpose of these orders education upto the senior level shall be treated as school education.

(vii) "Secondary Classes" means Classes VI to X.

(viii) "Tuition Fee" means tuition fee payable and actually paid, and includes :—

(i) Science fee.

(ii) Laboratory fee in case Science fee is not separately charged.

(iii) Special fee charged for agriculture as an elective additional subject and

(iv) any fee charged for subject like music which are taught as part of the regular school curriculum or subject requiring practical work under the programme of work experience.

Provided that if tuition fee charged from a Science student is higher than that charged from a non-science student, science fee, though separately charged, shall not be included in tuition fee for the purpose of these orders.

**Explanation :**

"Tuition fee" does not, however, include—

(i) Domestic Science fund charges.

(ii) Library fee,

(iii) Games fee,

(iv) Admission fee and

(v) Extra curricular activity fee.

**General Conditions :****4. Eligibility :**

(1) Subject to provisions of Regulation No. 11 to 24, all employee of the Board except persons in casual or daily rated or part time employment without and pay limit shall be eligible to drawn children's educational assistance, reimbursement of tuition fee and hostel subsidy.



5. (1) In case both wife and husband are employees of the Board and are governed by the provisions of these Regulations, the children's educational allowance or reimbursement of tuition fee or hostel subsidy as the case may be shall be admissible to one of them only.

(2) In case the wife or husband of an employee of the Board is employed outside the Port service the employee of the Board shall be able to draw the allowance or reimbursement or subsidy under these regulations, only if his/her spouse is not entitled to the benefit of any such allowance or reimbursement of subsidy from his/her employer and a declaration to that effect shall be obtained from the employee.

6. (1) The children's educational allowance or the reimbursement or tuition fees or hostel subsidy shall be admissible to employee of the Board while he/she is on duty or is under suspension or is on leave (including extra ordinary leave).

Provided that during any period which is treated as "Dies-non", the employee of the Board shall not be eligible for the allowance/reimbursement/subsidy for the period.

(2) If an employee of the Board dies or ceases to be in service by reason of retirement, resignation, discharge, dismissal or removal from service in the course of an academic year, the allowance or reimbursement or hostel subsidy shall be admissible till the end of academic year in which the event takes place.

7. Children's Educational Allowance, Reimbursement of Tuition Fee or Hostel Subsidy shall be admissible only in respect of children's between the age limits of 5 and 20 years. An employee of the Board shall not be eligible to draw children's educational allowance, reimbursement of tuition fee or hostel subsidy for a child for more than two academic years in the same class.

8. Assistance under these Regulations shall be available upto 3 children born upto 31-12-1987 and shall be restricted to two children born thereafter.

Provided that where an employee of the Board claims children's education allowance in respect of some of his children and hostel subsidy in respect of other children, the total number of children in respect of whom the allowance or subsidy is drawn shall not exceed two.

9. The children's educational allowance, reimbursement of tuition fee or hostel subsidy, as the case may be, shall be admissible to employee of the Board in respect of a child only if the child attends the school regularly.

Provided that no such allowance, reimbursement of tuition fee or hostel subsidy, shall be admissible in any case where the period of absence from the school without proper leave exceeds one month notwithstanding that the name of the child remains on the roll of the school.

10. The children's educational allowance, reimbursement of tuition fee, or hostel subsidy as the case

may be, shall be admissible to employee of the Board in respect of his children regardless of the fact that any scholarship is received provided that if freeship is awarded reimbursement of tuition fee/hostel subsidy shall be admissible only to the extent of fee actually paid.

#### Children's Educational Allowance

11. (1) An employee of the Board is eligible to draw children's educational allowance when he is compelled to send his child to a school away from the station at which he is posted and/or residing owing to the absence of a school of the requisite standard at that station.

(2) For the purpose of this order, the following schools shall not be deemed to be schools of the requisite standard :—

- (a) In so far as an Anglo-Indian child is concerned a school not run by the Anglo-Indian community or a school not affiliated to the council for Indian School Certificate Examination of the Indian Council of Secondary Education.
- (b) A school run by a body of certain religious persuasion which the child is prevented by the tenets of his religious persuasion from attending due to religious instructions being compulsorily imparted in a such a school and
- (c) A school where teaching is conducted in a language distinct from the language of the child.

**Explanation (1).**—The language of the child will be medium of instruction, in the school where the child was getting education earlier and in the case of child admitted in a school for the first time the mother tongue of the child by birth or by adoption.

**Explanation (2).**—The admissibility of children's educational allowance will have to be determined with reference to the standard of the school viz., Primary, Secondary or Higher Secondary or Senior Secondary and the medium of instruction and the language of the child and not to the absence of any particular subject in a particular institution.

12. The allowance shall be admissible to an employee of the Board at a station where there is no school of the requisite standard, only if the nearest school of such standard is so situated that there is no convenient train or bus service to take the child from his residence near the time of the opening of the school and bring him back not too long after the school is closed for the day and the journey by such train/bus service takes more than an hour.

13. If an employee of the Board is transferred from a station where there is no school of the requisite standard to a station where there is such a school and if he was in receipt of the allowance at the former station in respect of any child he shall remain eligible for such allowance until the close of the academic year the school in which his child was studying

at the time of his transfer, provided the child continue for that period in that school.

14. If a child of an employee of the Board is denied admission to a school of the 'requisite standard' at the station, at which the employee is posted and/or residing because of there being no vacancy, or any other reasons, and child is, compelled to attend a school away from the employee's place of posting and/or residence, the employee shall be entitled to the allowance as if there were no school of the requisite standard at that station.

**Explanation.**—The availability of vacancy in a school shall be determined with reference to the position existing at the time of the admission of the child in the school, whether it be at the start or in the middle of the session, in consultation with the competent educational authorities of the area and not on the basis of the certificate of the school authorities.

15. An employee in receipt of the allowance shall continue to be eligible to draw such allowance during any period, not exceeding four months.

(1) When he may go and stay with the child in respect of whom the allowance is drawn while on leave or during suspension or temporary transfer.

(2) When the child may come to live with the employee provided it is certified by a registered medical practitioner that the child is forced to remain away from studies due to illness, and

(3) When the child may come to live with the employee during vacation, provided the child continues to be on the rolls of the school.

16. The allowance shall be admissible to an employee at the following rates:

Primary, Secondary and Higher Secondary Classes—  
I to XII : Rs. 50/- per month per child.

17. (1) The allowance shall be admissible to an employee throughout the year notwithstanding that no tuition fee is paid during the vacation.

(2) In the case of a child who is successful at the final secondary/higher secondary/senior secondary examination, the allowance shall be admissible to the employee upto the end of the month in which the examination is completed or upto the end of one month upto which the school fees are charged, whichever is later.

(3) In the case of a child who fails in the final secondary/higher secondary/senior secondary examination, but resumes his studies the allowance shall be admissible to the employee for the period of vacation intervening provided that fees are paid for the period of vacation.

#### Reimbursement of Tuition Fee

18. An employee shall be eligible to the reimbursement of tuition fee payable and actually paid in respect of his child provided that no children's educational allowance under these regulations is admissible to him.

19. The tuition fee payable and actually paid by an employee in respect of his child may be reimbursed subject to the following :

- (a) Classes I to X—Rs. 20/- p.m. per child.
- (b) Classes XI to XII—Rs. 25/- p.m. per child.
- (c) Classes I to XII—in respect of physically handicapped and mentally retarded children—Rs. 50/- p.m. per child.

NOTE : 'Science fee' upto the limit of Rs. 5/- p.m. will be reimbursable in addition to the tuition fee in respect of children studying in Classes IX to XII and offering science subjects.

20. The reimbursement of tuition fee charged by a college run by a University or affiliated to a University for Pre-University/first year class of an intermediate college or of a technical college or first year class of polytechnic or for a correspondence course shall, however, be reimbursed in full subject to their being restricted to the rates prescribed by Govt. college for corresponding classes.

"In cases where minimum qualification for admission in the two year diploma course in polytechnics is 10th Class of the revised pattern of education and the student joins the polytechnic after passing X class of the revised pattern of education, the reimbursement of tuition fees shall also be allowed for the I and the II year classes of the above course".

21. Notwithstanding anything to the contrary in these orders, tuition fee payable and paid in respect of physically handicapped or a mentally retarded child of an employee shall be reimbursed subject to the following conditions :—

- (a) The institution in which the child is studying is one which is recognised or approved or aided by the Central Govt. or State Govt. or Union Territory Administration.
- (b) The fee charged are approved by the Central Govt. or State Govt. or Union Territory Administration as the case may be.

**Explanation :**—If the institution is recognised or approved or aided but the fees charged are not approved by Central or State Govt. or Union Territory Administration, the fee reimbursable shall be subject to ceiling of Rs. 50/- p.m.  
**Hostel Subsidy**

22. An employee shall be eligible to the grant of subsidy at the rate of Rs. 150/- p.m. per child, if because of his transfer he is obliged to keep his children in the hostel of a residential school far away from the station at which he is posted and/or is residing.

However, if the date of admission to the hostel is earlier than the date of transfer, and if such admission is made in anticipation of the transfer, the hostel subsidy may be made from the effective date of transfer.

23. The hostel subsidy shall be payable upto 10 + 2 stage in States and Union Territories, where the pattern of

10 + 2 + 3 has been adopted and upto higher secondary and senior secondary stage in other States and Union Territories irrespective of the fact that the children study in a Kendriya Vidyalaya or any other recognised school.

24. The hostel subsidy shall not be admissible in respect of a child for whom children's educational allowance is drawn by an employee.

**Procedure for Payment of Children's Educational Allowance Reimbursement of Tuition Fees and Hostel Subsidy.**

25. An employee, claiming children's educational allowance, reimbursement of tuition fees or hostel subsidy shall furnish a certificate in the prescribed forms 1, 2, 3 and 4 as the case may be, to the Head of Office at the time of preferring his initial claim and thereafter in the months of March and July every year. Where the employee is himself the Head of the Office, he shall furnish the certificate to the next higher authorities.

**Note :** For reimbursement of tuition fees to an employee, a certificate from the Head of the Institution where the child is studying need not be insisted upon. However, at the time of accepting the initial claims production of the cash receipt given by the school or the counterfoil of the bank credit voucher, if the tuition's fee is paid through bank by the employee as a proof of having actually paid the tuition fee will be sufficient.

For the subsequent occasions, a declaration from the employee to the effect that he continue to incur the expenditure on tuition fee etc. should be accepted. The employee may also be asked to certify that his child/children is/are actually studying in a recognised school and that he is actually incurring expenditure on tuition fee.

26. The head of office in regard to employees working in his office and the next higher authority in regard to Head of Office shall, after making such enquiry as may be

considered necessary issue a certificate indicating the amount of allowance admissible to the employee on the basis of which the allowance shall be drawn.

Provided that in the case of children's educational allowance it shall be permissible for the allowance being drawn on a provisional basis, pending verification as above, for short periods not exceeding three months subject to an undertaking being obtained from the employee that, if, as a result of verification, if it established that a school of the requisite standard does exist at the station of posting/residence or near such station as referred to in Regulation No. 12, he shall refund the allowance paid to him.

Provided further that the Head of Office or the next higher authority, as the case may be may at his discretion, make enquiry at periodic intervals regarding admissibility of assistance under these orders.

27. The Head of Office shall certify on the pay bill that the certificates mentioned in Regulation No. 26 above have been obtained in respect of employees covered in the pay bill.

28. An employee transferred from one station to another shall furnish a fresh certificate at the new station in case he continues to be eligible to draw children's educational allowance or hostel subsidy.

29. The head of office should maintain a suitable record of the claims received, admitted/rejected and reimbursed in respect of each Port employee and make it available to the Financial Adviser and Chief Accounts Officer along with the certificate and information furnished by the Port employee, the receipts of educational authorities in support of the claims preferred by them and other documents, if any. The record to be maintained shall be in the form as in Form No. 5.

[F. No. PR-12016/40/94-PEI]

K. V. RAO, Jt. Secy.